अपीलीय सिविल

समक्ष दया कृष्ण महाजन और गुरदेव सिंह, जे.

ब्रह्मानंद और अन्य,-अपीलकर्ता

बनाम

शिव कुमार और अन्य,-प्रतिवादी

सिविल विविध. 182/सी 1967

आर.एस. 39; 1967 का A.L64I

15 जनवरी 1968.

परिसीमा अधिनियम (1963 का XXXVI)–एस. 5 और 12-नियमित दूसरी अपील-दाखिल करना-ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रति प्राप्त करने में लगने वाला समय-क्या बाहर रखा जाए-ऐसा समय-क्या धारा 5 के तहत माफ किया जा सकता है-माफी के कारण नहीं बताए गए-प्रत्येक दिन की देरी स्पष्ट नहीं किया गया है - क्षमा - क्या दी जा सकती है - क्षमा प्रदान करना - परिस्थितियों के अंतर्गत - बताया गया है।

माना गया, (डी.के. महाजन, जे.).- कि नियमित दूसरी अपील दायर करने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 के तहत बाहर नहीं किया जा सकता है।

माना गया कि कुछ मामलों में, ट्रायल कोर्ट के फैसले को सीमा से बाहर दाखिल करने में हुई देरी को अधिनियम की धारा 5 के तहत माफ किया जा सकता है। लेकिन जब धारा के तहत देरी को माफ करने के लिए आवेदन में कोई कारण नहीं बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रति के लिए आवेदन देर से क्यों दायर किया गया था और प्रत्येक दिन की देरी की व्याख्या नहीं की गई है, तो ऐसी माफी के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

माना गया (गुरदेव सिंह, जे.) - धारा 12 या सीमा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलकर्ता को दूसरी अपील में फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च किए गए समय के बहिष्कार का दावा करने का अधिकार देता है। ट्रायल कोर्ट के और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI में उच्च न्यायालय द्वारा जोड़े गए नियम 2 के तहत भी उसे ऐसी कोई रियायत की अनुमति नहीं है।

माना गया कि चूंकि दूसरी अपील में अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार परिसीमा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ ट्रायल कोर्ट के फैसले की एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता है। इस बात पर विवाद किया जा सकता है कि यदि उसे अधिनियम की अनुसूची 1 द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर अपील दायर करने से रोका जाता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति उसे प्रदान नहीं की गई है, तो यह धारा के तहत पर्याप्त कारण बनता है। देरी को माफ करने और निर्धारित अवधि के बाद अपील स्वीकार करने के लिए अधिनियम की धारा 5। हालाँकि, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का बहिष्कार, फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने और अपील की गई डिक्री प्राप्त करने में लगने वाले समय के समान नहीं है। जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 12 के तहत हकदार है। धारा 12 के तहत

वादी को उस समय के बहिष्कार का दावा करने का अधिकार है जो उसने निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में खर्च किया है, जिसके खिलाफ अपील की गई है, और भले ही वह अपील के लिए निर्धारित सीमा अवधि के भीतर उन प्रतियां प्राप्त करता है, वह है। निर्धारित अवधि के भीतर अपनी अपील शुरू करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन, यदि वह चाहे तो, उस समय के लाभ का दावा करने के लिए इंतजार कर सकता है जो उसने वास्तव में इन प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने में खर्च किया था। हालाँकि, अधिनियम की धारा 5 के तहत

देरी को केवल तभी माफ किया जा सकता है जब अपीलकर्ता अदालत को संतुष्ट कर दे कि परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर अपील शुरू न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे। यद्यपि अपील के लिए निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति से पहले ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने में नकल विभाग की विफलता को उसके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील शुरू नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा। अधिनियम, फिर भी अधिनियम की धारा 5 के तहत वह ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में खर्च की गई पूरी अवधि को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन से निपटने में, इस तथ्य के कारण हुई देरी को माफ करने के लिए कि ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में समय व्यतीत हुआ, अदालत स्वाभाविक रूप से जांच करेगी कि अपील दर्ज करने में कितनी देरी हुई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले की ऐसी प्रति की अनुपलब्धता के कारण हुआ। अधिनियम की धारा 5 का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपीलकर्ता को निर्धारित सीमा अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण बताना होगा। धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त अपील दायर करने की परिसीमा अवधि बढ़ा दी जाए और इस अपील को समय के भीतर माना जाए।

जे.के. शर्मा, अपीलकर्ताओं के लिए एक वकील।

प्रतिवादियों की ओर से आर.एन.मित्तल, अधिवक्ता।

ब्रह्मानंद और अन्य, बनाम शिव कुमार और अन्य, एस

महाजन, जे.-

यह आदेश सिविल विविध क्रमांक 182-सी सन् 1967 का नियमित द्वितीय अपील क्रमांक 64 सन् 1967 में निराकरण करेगा।

यह आवेदन सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि अपील, जो सीमा से बाहर दायर की गई है, इसे दाखिल करने में हुई देरी को माफ करके सीमा के भीतर इलाज किया जाएगा।

सीमा के प्रश्न को समझने के लिए, कुछ प्रमुख तथ्यों को सामने रखना आवश्यक है। जिस डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है वह 3 जून, 1966 को पारित की गई थी। अपील वास्तव में इस न्यायालय में 14 दिसंबर, 1966 को प्रस्तुत की गई थी। निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। 1 जुलाई, 1966; और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे 31 अगस्त, 1966 को वितरित किया गया था, क्योंकि प्रतिलिपि उसी तिथि को पूरी और सत्यापित की गई थी। इसलिए, अपीलकर्ता दूसरी याचिका दायर करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित अवधि के अलावा सीमा अधिनियम की धारा 12 के तहत बासठ दिनों की एक और अवधि का हकदार था। अपील, यानी नब्बे दिन. कुल मिलाकर, जिस डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है उसके 152वें दिन अपील दायर की जा सकती है। यह अवधि 2 नवंबर, 1966 को समाप्त होती है। 2 नवंबर, 1966 तक अपील दायर नहीं की गई थी। इसका कारण यह बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के लिए एक आवेदन किया गया था और इसके बाद अपील दायर की गई थी यह प्राप्त किया गया था. इस प्रति के लिए खर्च की गई अवधि को ऊपर उल्लिखित 152 दिनों की अवधि में जोड़ने की मांग की गई है। सीमा अधिनियमकी धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की प्रार्थना की गई है। यह कहा गया है कि वर्तमान अपील दायर करने

की सीमा 25 अक्टूबर 1966 को विद्यमान थी, जब ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रति के लिए एक आवेदन किया गया था। यह निर्णय 7 दिसंबर, 1966 को तैयार हो गया था और अंततः 8 दिसंबर, 1966 को अपीलकर्ता को दिया गया था। उच्च न्यायालय के नियमों के तहत, ज्ञापन के साथ ट्रायल कोर्ट के फैसले की एक प्रति दाखिल करना आवश्यक है। अपील, और, इसलिए, अपीलकर्ता उस प्रति को प्राप्त करने में बिताए गए समय को अपील दायर करने की सीमा अवधि में जोड़ने का हकदार है।

यह अपरिहार्य है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को सीमा अधिनियम की धारा 12 के तहत बाहर नहीं रखा जा सकता है। मुझे इस विषय पर केवल प्रमुख मामले का उल्लेख करने की आवश्यकता है - नरसिंह**सहाय बनाम शेओ प्रसाद**। इसके विपरीत कोई निर्णय मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है। वास्तव में, इस निर्णय का लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है; और यह केवल धारा 5 के तहत है, कि कुछ मामलों में, ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सीमा से बाहर करने में देरी को माफ कर दिया गया है

देरी माफ करने के आवेदन में कोई कारण नहीं दिया गया है। वास्तव में, प्रतिलिपि अपीलकर्ता के हाथ में 8 दिसंबर, 1966 को आई और अपील 14 दिसंबर, 1966 को दायर की गई। 8 दिसंबर, 1966 के बीच की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। , और 14 दिसंबर, 1966। नियम अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक दिन की देरी को समझाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है. इसलिए, 8 दिसंबर, 1966 से 14 दिसंबर, 1966 के बीच देरी को माफ करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। इस संबंध में **जॉर्ज गौशाला बनाम बालक राम< का निर्णय देखें। /span>**. 378**A.I.R 1939 लाह** () **सरदार पृथी पाल सिंह बनाम पंडित हंस राज और अन्य**, और . 717**A.I.R 1927 लाह** ()

यह विवादित नहीं है कि अपील सीमा से बाहर दायर की गई है; और इसे 2 नवंबर, 1966 को दाखिल किया जाना था, जबकि इसे 14 दिसंबर, 1966 को दाखिल किया गया है। हालांकि, यह दावा किया गया है कि ट्रायल कोर्ट की प्रति प्राप्त करने में समय व्यतीत हुआ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्णय को माफ किया जाए। बिताया गया समय 25 अक्टूबर, 1966 से 8 दिसंबर, 1966 तक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले की

प्रति के लिए आवेदन तब दायर किया गया था जब अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के लिए आवेदन इतने विलंब से क्यों दायर किया गया था। इसे अप्पल दाखिल करने के लिए दी गई नब्बे दिनों की अवधि के भीतर दाखिल नहीं किया गया था। इसलिए, इस मामले के तथ्यों पर हमारा स्पष्ट मानना है कि 25 अक्टूबर, 1966 और 8 दिसंबर, 1966 के बीच देरी को माफ करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। **गुरदित सिंह बनाम चरण दास** () **A.I.R 1922 लैब में। 415**, लाहौर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की एक प्रति प्राप्त करने में बिताए गए छह दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। इस तरह निपटाया गया मामला:–

"*****

निश्चित रूप से सीमा अधिनियम की धारा 12 के तहत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन उनका आग्रह है कि उनकी सहायता के लिए धारा 5 को लागू किया जा सकता है। हालाँकि, हम यह देखने में असमर्थ हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। यदि अपीलकर्ता प्रारंभ में ट्रायल कोर्ट के फैसले की एक प्रति प्राप्त करने में विफल रहा और सीमा अवधि के अंत में इस प्रति को प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया, तो हमें लगता है कि धारा 5 का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, उन्होंने यह प्रति जून की शुरुआत में प्राप्त कर ली थी, और हम यह मानने का कोई कारण नहीं देख पा रहे हैं कि इस मामले में देरी के लिए कोई पर्याप्त कारण था। हम मानते हैं कि अपीलकर्ता ने घोर लापरवाही बरती है। वह 22 जून को लायलपुर जा सकते थे, और यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो 90 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती थी। इसके बजाय उन्होंने अपने वकील को डाक से आवेदन करने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनका आवेदन 2 जुलाई तक लायलपुर के नकल विभाग तक नहीं पहुंचा। हमने 9**I.C 381, 14 I.C 403, 50 I.C 760 और 44 I.C 831** प्राधिकारियों पर विधिवत विचार किया है, जिनसे हम सहमत हैं।

में **मदन गोपाल बनाम मलावा राम** () **A.I.R 1923 लाहौर 96**< a i=4>. जिस मामले के तथ्य कुछ हद तक वर्तमान मामले के तथ्यों के समान हैं, धारा 5 के तहत एक प्रार्थना को निम्नलिखित शब्दों में अस्वीकार कर दिया गया था:–

"*****

श्रीमान. अपीलकर्ता के लिए बद्री दास ने तर्क दिया है कि चूंकि, इस न्यायालय के नियमों के अनुसार, अपीलकर्ता पर पहले न्यायालय के फैसले की एक प्रति भी दाखिल करना अनिवार्य है, इस मामले में अपीलकर्ता बिताई गई अवधि के लाभ का हकदार था। प्रथम न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त करने में। पहले न्यायालय के फैसले की प्रति के लिए आवेदन 20 जुलाई, 1921 को किया गया था और इसे 29 जुलाई, 1921 तक वितरित नहीं किया गया था। यदि अपीलकर्ता को यह अवधि दी जाती, तो उसकी अपील निश्चित रूप से होती समय के भीतर. लिमिटेशन एक्टकी धारा 12 के खंड (3) में यह प्रावधान है कि जहां किसी डिक्री के खिलाफ अपील की जाती है या उसकी समीक्षा की मांग की जाती है, उसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय लगता है। जिस निर्णय पर यह आधारित है उसकी प्रति भी शामिल नहीं की जाएगी। अब, इस मामले में, जिस डिक्री की अपील की गई है वह अपीलीय न्यायालय की डिक्री है। इसलिए, केवल उस निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाना चाहिए, जिस पर डिक्री के खिलाफ अपील की गई है। मुझे पता है कि इस न्यायालय ने एक नियम बनाया है जिससे अपील के ज्ञापन के साथ प्रथम न्यायालय के फैसले की एक प्रति दाखिल करना आवश्यक हो गया है। इस न्यायालय के पास संहिता की धारा 122 के अनुसार **सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के नियमों को बदलने, संशोधित करने और जोड़ने की शक्ति है; लेकिन यह परिसीमा अधिनियम द्वारा प्रदान की गई परिसीमा की अवधि को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। कानून का यह दृष्टिकोण नरसिंह साहा बनाम शेओ प्रसाद** () (1918) 40 ऑल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा समर्थित है। 1. श्री बद्री दास ने मुझसे सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत इस मामले में परिसीमा की अवधि बढ़ाने और अपील को समय के भीतर मानने के लिए कहा है। , लेकिन मुझे ऐसा करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखता। जिस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, वह 11 अप्रैल,

1921 को सुनाया गया था, और अपीलकर्ता ने 4 जुलाई, 1921 तक फैसले और डिक्री की प्रति के लिए आवेदन नहीं किया था। एक अदालत ऐसे वादी के प्रति दया दिखाने के लिए बाध्य नहीं है जो मांग करने में तत्पर नहीं है। उसका उपाय.

*****"

चूहर मल बनाम बीरा राम और अन्य () में उसी विद्वान न्यायाधीश का निर्णय भी इसी आशय का है। **A.I.R 1923 लाह. 461**; और **बाबू सिंह और अन्य बनाम मंगत राय और अन्य** () **A.I.R 1927 लाह. 192.**

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री शर्मा ने तब तर्क दिया कि इस न्यायालय की प्रथा ट्रायल काउंट के फैसले की प्रति के बिना अपील स्वीकार नहीं करना है। हमें डर है, ऐसी कोई प्रथा नहीं है.

ऊपर दर्ज कारणों से, हमें इस अपील को सीमा-बाधित मानकर खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

गुरदेव सिंह, जे.–मैं सहमत हूं कि इस अपील को समयबाधित मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसमें शामिल प्रश्न के महत्व और फैसले और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में खर्च किए गए समय को बाहर करने के अपीलकर्ता के अधिकार के बारे में व्याप्त गलत धारणा को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने स्वयं के कारण बताना चाहूंगा।

जिस डिक्री के खिलाफ अपील की गई थी, वह 3 जून, 1966 को पारित की गई थी। डिक्री की प्रमाणित प्रतियां और जिस निर्णय पर यह आधारित है, अपीलकर्ता द्वारा 90 दिनों के भीतर, अपील के लिए निर्धारित सीमा अवधि के भीतर आवेदन किया गया था। और फैसले की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और जिस डिक्री के खिलाफ अपील की गई थी, उसे प्राप्त करने में बिताए गए 62 दिनों को छोड़कर, के मद्देनजर अपील 152वें दिन पर शुरू की जा सकती थी, जो 2 नवंबर, 1966 को समाप्त हो गई थी। परिसीमा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान।हालाँकि, ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति के रूप में अपील उस तारीख तक शुरू नहीं की जा सकी, जो इस न्यायालय के नियमों के तहत थी अपील के ज्ञापन के साथ

दाखिल करने के लिए तैयार नहीं था। ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन 25 अक्टूबर, 1966 को किया गया था, यानी डिक्री की तारीख से 152 दिन की समाप्ति से पहले। ट्रायल कोर्ट के फैसले की यह प्रमाणित प्रति 7 दिसंबर, 1965 को तैयार हो गई थी, हालांकि सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन में दिए गए कथनों के अनुसार, यह उन्हें 8 दिसंबर, 1965 को सौंपा गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले की इस प्रमाणित प्रति के साथ-साथ डिक्री और फैसले की प्रमाणित प्रतियों के साथ अपील, जिसके खिलाफ अपील की गई थी, केवल इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। 14 दिसंबर, 1966 को। अपीलकर्ता ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी के लिए आवेदन किया और आग्रह किया कि देरी इस तथ्य के कारण हुई थी कि नकल विभाग ने अपील के ज्ञापन के साथ दाखिल करने के लिए आवश्यक प्रमाणित प्रतियां तैयार करने और उन्हें उपलब्ध कराने में काफी समय लिया था। साथ ही वह दोनों न्यायालयों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में खर्च की गई पूरी अवधि की कटौती का भी हकदार है, और यदि उसे इसकी अनुमति दी जाती है, तो उसकी अपील समय के भीतर है। इस प्रकार, विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न है:–

"क्या अपीलकर्ता मुकदमे और अपीलीय अदालतों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च की गई पूरी अवधि के बहिष्कार का हकदार है, और भले ही यह माना जाए कि वह इसका हकदार नहीं था ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रति प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च की गई अवधि को घटाएं, क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में खर्च किए गए समय को उसे धारा के तहत अनुमति दी जा सकती है भारतीय सीमा अधिनियम के 5?"

एकमात्र प्रावधान जिसके तहत एक वादी कुछ निर्णयों और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च किए गए समय का दावा कर सकता है, वह धारा 12 की **उप-धारा (3) में निहित है। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है),**जो परिसीमा की अवधि की गणना में यह निर्धारित करता है।

"जहां किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील की जाती है या उसे संशोधित या समीक्षा करने की मांग की जाती है, या जहां किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है, उस निर्णय की एक प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय जिस पर डिक्री या आदेश है स्थापित को भी बाहर रखा जाएगा।"

अभिव्यक्ति "समय अपेक्षित" का अर्थ अब अच्छी तरह से तय हो गया है। इसका मतलब है उचित और यथोचित समय की आवश्यकता। जिजिभोय एन. सुर्टी बनाम टी.एस. चेट्टियार () A.I.R 1928 P.C 103 में, लॉर्ड फिलिमोर ने इस संबंध में कहा:–

"'अपेक्षित' शब्द एक मजबूत शब्द है; इसे 'आवश्यक' शब्द से कुछ अधिक अर्थ वाला माना जा सकता है। इसका अर्थ है 'उचित रूप से आवश्यक', और यह अपीलकर्ता या अपीलकर्ता के वकील पर यह दिखाने की आवश्यकता डालता है कि निर्धारित अवधि से अधिक देरी का कोई भी हिस्सा उसके डिफ़ॉल्ट के कारण नहीं है।'

इससे पहले प्रमथ नाथ रॉय बनाम विलियम आर्थर ली () **A.I.R 1922 P.C 322**, न्यायिक समिति के उनके आधिपत्य ने फैसला सुनाया था कि अधिनियम के तहत किसी भी अवधि को अपेक्षित नहीं माना जा सकता है, जिसे समाप्त होने की आवश्यकता नहीं है; यदि अपीलकर्ता ने आदेश प्राप्त करने के लिए उचित और उचित कदम उठाए थे।

हमारे सामने अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियों के लिए 1 जुलाई, 1966 को आवेदन किया था, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई थी, और उसने 31 अगस्त को इसे प्राप्त कर लिया। 1966. लिमिटेशन एक्ट की धारा 12 की उप-धारा (3) के तहत, जिसे ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, वह अधिकार के मामले में हकदार है उसकी अपील के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करने में उसके द्वारा अपील किए गए फैसले और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में खर्च की गई 62 दिनों की अवधि को हटा दें। इस प्रकार, वह डिक्री के खिलाफ अपील की तारीख से 152 दिनों के भीतर, यानी 2 नवंबर, 1966 को या उससे पहले अपील दायर कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के **नियम 1 के तहत,** अपील के ज्ञापन के साथ "की एक प्रति संलग्न होना आवश्यक है" डिक्री के खिलाफ अपील की गई और (जब तक कि अपीलीय अदालत उससे छूट नहीं देती) उस फैसले की जिस पर यह आधारित है।" दूसरी अपील, या अपीलीय डिक्री से अपील के मामले में, इस न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLII में नियम 2 जोड़ा गया है। जैसा कि 19 मार्च, 1926, प्रदान करता है:–

"**आदेश 41, नियम 1,** में निर्दिष्ट प्रतियों के अलावा, अपील के ज्ञापन के साथ निर्णय की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी प्रथम दृष्टया न्यायालय का, जब तक कि अपीलीय न्यायालय इससे छूट नहीं देता।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस अपील की उचित प्रस्तुति के लिए अपीलकर्ता को न केवल प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करनी थीं, बल्कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय की भी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करनी थीं। जहां तक फैसले और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च किए गए समय का सवाल है, जिसके खिलाफ अपील की गई है, जैसा कि पहले देखा गया है, अपीलकर्ता को और चूंकि उन्होंने उन प्रतियों को प्राप्त करने में 62 दिन बिताए थे, इसलिए वह 2 नवंबर, 1966 तक इंतजार कर सकते थे। उसकी अपील स्थापित करना। हालाँकि, सीमा अधिनियम की धारा 12 या किसी अन्य प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अपीलकर्ता को दूसरी अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च किए गए समय के बहिष्कार का दावा करने का अधिकार देता हो और न ही ऐसी रियायत उसे इस न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLII में जोड़े गए नियम 2 के तहत भी दी जाती है। इस संबंध में, **मदन गोपाल बनाम मलावा राम** () **ए.आई.आर. 1923 लाहौर 96**, जिसका उल्लेख मेरे विद्वान भाई ने अपने निर्णय के दौरान किया है, प्रासंगिक हैं। रऊफ़ के बारे में, जे. ने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए कहा:–

"मुझे पता है कि इस न्यायालय ने एक नियम बनाया है जिससे अपील के ज्ञापन के साथ प्रथम न्यायालय के फैसले की एक प्रति दाखिल करना आवश्यक हो गया है। इस न्यायालय के पास संहिता की धारा 122 के अनुसार **सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के नियमों**

को बदलने, संशोधित करने और जोड़ने की शक्ति है; लेकिन यह परिसीमा अधिनियम द्वारा प्रदान की गई परिसीमा की अवधि को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। कानून का यह दृष्टिकोण नरसिंह साहा बनाम शेओ प्रसाद () (1918) 40 ऑल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा समर्थित है। 1.

चूंकि दूसरी अपील में अपीलकर्ता को इस न्यायालय के नियमों के अनुसार उप-खंड में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ ट्रायल कोर्ट के फैसले की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। 3) सीमा अधिनियम की धारा 12 के,इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि यदि उसे इस तथ्य के कारण कि ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है, यह धारा के तहत पर्याप्त कारण बनता है देरी को माफ करने और निर्धारित अवधि के बाद अपील स्वीकार करने के लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5। [भारत संघ बनाम फर्म बलवंत सिंह जसवन्त सिंह () **I.L.R 1956 पुन). 1129 (एफ.बी.) ए.आई.आर. 1957 पुंज। 27 (F.B**)]. हालाँकि, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय के समान, जिसके खिलाफ अपील की गई है, जिसके लिए एक अपीलकर्ता सीमा अधिनियम की धारा 12 के तहत हकदार है। धारा 12के तहत वादी को उस समय के बहिष्कार का दावा करने का अधिकार है जो उसने निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में खर्च किया है, जिसके खिलाफ अपील की गई है, और भले ही वह उस अवधि के भीतर उन प्रतियां प्राप्त कर ले। अपील के लिए निर्धारित सीमा के कारण, वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी अपील दायर करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन, यदि वह चाहे तो, उस समय के लाभ का दावा करने के लिए इंतजार कर सकता है जो उसने वास्तव में इन प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने में खर्च किया था। हालाँकि, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत, देरी को केवल तभी माफ किया जा सकता है, जब अपीलकर्ता ने अदालत को संतुष्ट किया कि उसके द्वारा मामले की सुनवाई न करने के लिए पर्याप्त कारण थे। भारतीय सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर अपील करें। यद्यपि अपील के लिए निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति से पहले ट्रायल कोर्ट के फैसले

की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने में नकल विभाग की विफलता को उसके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील शुरू नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा। अधिनियम, फिर भी अधिनियम की धारा 5 के तहत वह ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में खर्च की गई पूरी अवधि को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन से निपटने में, इस तथ्य के कारण हुई देरी को माफ करने के लिए कि ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में समय व्यतीत हुआ, स्वाभाविक रूप से यह जांच करेगा कि अपील दर्ज करने में कितनी देरी हुई। ट्रायल कोर्ट के फैसले की ऐसी प्रति की अनुपलब्धता।

डिक्री और निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगने वाले समय का लाभ उठाने के लिए, अपीलकर्ता को सीमा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले ऐसी प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करना होगा। यदि वह सीमा की पूरी निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद प्रतियों के लिए आवेदन करता है, तो निश्चित रूप से वह सीमा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है। सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत समय विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। अपीलकर्ता का दावा है कि वह 25 अक्टूबर, 1966 और 8 दिसंबर, 1966 के बीच की पूरी अवधि का हकदार है, जो उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में खर्च की थी, और यदि इस पूरी अवधि को समय के साथ हटा दिया जाए निर्णय और डिक्री की प्रतियां प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च की गई समय सीमा की निर्धारित अवधि से, उसकी अपील समय के भीतर ही की गई थी, क्योंकि निर्णय की प्रतियां प्राप्त करने में खर्च किए गए समय को छोड़कर सीमा की अवधि बढ़ा दी गई थी और डिक्री, जिसे अपील के साथ दायर किया जाना था, 17 नवंबर, 1966 को समाप्त हो गई। यह विवाद स्पष्ट रूप से अस्थिर है। जैसा कि पहले देखा गया है, सीमा अधिनियम की धारा 5, पी. सी. पंडित, जे. ने फैसला सुनाया कि एक अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च किए गए समय का दावा कर सकता है, जहां प्रतिलिपि के लिए आवेदन उसके द्वारा किया जाता है। परिसीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति, लेकिन उसके द्वारा अपील किए गए फैसले और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त

करने में बिताए गए समय को घटाने के बाद विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले। इस निर्णय के मद्देनजर, अपीलकर्ता 25 अक्टूबर, 1966 को ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार में था, और यदि उस प्रति की अनुपलब्धता के कारण उसे वर्तमान अपील दायर करने से रोका गया था, उसे A.I.R 1961 पुंज. 503=**I.L.R (1961) 2 पुंज में। 518** () बटन सिंह और अन्य बनाम नाथू बिरजू क्योंकि सीमा अवधि समाप्त होने के बाद और अपील पहले से ही समय से बाधित हो गई है, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगने वाले समय का बहिष्कार, जिसके लिए सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन किया गया था, सीमा न बचाएं. , अपीलकर्ता को निर्धारित सीमा अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण बताना होगा। हमारे सामने मौजूद मामले में, ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति, जिसके लिए अपीलकर्ता ने 25 अक्टूबर, 1966 को आवेदन किया था, 7 दिसंबर, 1966 को तैयार और सत्यापित थी। कॉपी में यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह कब था अपीलकर्ता को सौंप दी गई, लेकिन भले ही हम उनकी इस बात को स्वीकार कर लें कि यह उनके हाथ में 8 दिसंबर, 1966 को ही आई थी, तथ्य यह है कि इसके छह दिन बाद उन्होंने यह अपील दायर की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि 8 दिसंबर, 1966 तक, अपीलकर्ता को अपनी अपील दायर करने से रोका गया था क्योंकि उस दिन से पहले प्रमाणित प्रति उसे प्रदान नहीं की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रति की अनुपलब्धता उन्हें 8 दिसंबर, 1966 और 14 दिसंबर, 1966 के बीच छह दिनों की अवधि के दौरान अपील दायर करने से रोका गया था। परिसीमा की धारा 5 के तहत अपीलकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कुछ भी नहीं है। अधिनियम, या इसके साथ संलग्न हलफनामा, यह बताने के लिए कि अपीलकर्ता ने 8 दिसंबर, 1966 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद भी अपनी अपील शुरू करने के लिए 14 दिसंबर, 1966 तक इंतजार क्यों किया। यह अब है अच्छी तरह से निपटाया गया, और अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया है, कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ उठाने के लिए, अपीलकर्ता को प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण देना होगा। **राम लाल और अन्य बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड** () A.I.R 1962 S.C 361, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में

निहित विवेक के प्रयोग से निपटते समय, गजेंद्रगडकर, जे., (जैसा कि वह तब वह) न्यायालय के लिए बोल रहा था, इस प्रकार देखा गया:–

“हालाँकि, इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी कोई पक्ष अधिकार के तौर पर प्रश्न में देरी की माफ़ी का हकदार नहीं है। पर्याप्त कारण का सबूत धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक शर्त है। यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है, तो आगे कुछ नहीं करना होगा; देरी को माफ करने के आवेदन को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है, तो न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या उसे अपने विवेक से देरी को माफ करना चाहिए। मामले का यह पहलू स्वाभाविक रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का परिचय देता है और यह इस स्तर पर है कि पार्टी के परिश्रम या उसकी प्रामाणिकता पर विचार किया जा सकता है; लेकिन पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से केवल ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होगा जिन्हें न्यायालय प्रासंगिक मान सकता है। यह इस जांच को उचित नहीं ठहरा सकता कि पार्टी इतने समय में भी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही। इस संबंध में हम यह बता सकते हैं कि जब न्यायालय परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत किए गए आवेदनों पर विचार कर रहा है, तो सद्भावना या उचित परिश्रम के विचार हमेशा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होते हैं।< a i=2> ऐसे आवेदनों से निपटने में न्यायालय को धारा 5 और 14 के संयुक्त प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा जाता है। इसलिए, हमारी राय में, धारा 14 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से सामग्री और प्रासंगिक बनाए गए विचार नहीं किए जा सकते हैं उसी सीमा तक और उसी तरीके से उन आवेदनों से निपटने में लागू किया जाना चाहिए जो धारा 14 के संदर्भ के बिना केवल धारा 5 के तहत तय किए जाते हैं।'

इस आधिकारिक घोषणा के आलोक में, हालांकि अपीलकर्ता को 25 अक्टूबर, 1966 से पहले ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने में अपनी विफलता को समझाने या उचित ठहराने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जबकि अवधि जिस फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील की गई है, उसकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगने वाले समय को छोड़कर,

धारा 12 के तहत बढ़ाई गई सीमा अभी भी विद्यमान थी, वह छह दिनों की देरी के लिए लेखांकन के अपने दायित्व से बच नहीं सकता है, जो उसने शुरू करने में ली थी। 8 दिसंबर, 1966 के बाद अपील, जब निर्णयों और डिक्री की सभी प्रमाणित प्रतियां, जिन्हें अपील के ज्ञापन के साथ दायर किया जाना आवश्यक था, उनके हाथ में थीं। लिमिटेशन एक्टकी धारा 5 के तहत, जहां ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रति की अनुपलब्धता दाखिल न करने का एकमात्र कारण बताया गया है निर्धारित अवधि के भीतर अपील करने पर, अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में उसके द्वारा खर्च की गई पूरी अवधि का दावा करने का हकदार नहीं है, बल्कि केवल उस अवधि का दावा करने का हकदार है जिसके दौरान वह प्रति उसे उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यदि प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद भी वह निष्क्रिय रहता है और फिर भी प्रतीक्षा करने का निर्णय लेता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है। जैसे ही ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति, जिसके अभाव में वह अपील दायर नहीं कर सका, उसके हाथ में आती है, उसे परिश्रमपूर्वक कार्य करना होता है और अपील दायर करनी होती है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने 8 दिसंबर 1966 को ट्रायल कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के तुरंत बाद अपनी अपील के साथ अदालत में न आने का कोई कारण नहीं बताया है। तदनुसार, मुझे लगता है कि वह नहीं है धारा 5 के लाभ का हकदार है, और उस धारा के तहत उसके आवेदन को खारिज करते हुए, उसकी अपील को समय से बाधित मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

आर.एन.एम.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा